पश्चिमी क्षेत्रीय सम्मेलन का उद्घाटन सत्र : डबल इंजन की सरकार किसानों को आत्मनिर्भर बनाने के लक्ष्य के साथ कर रही काम

कृषि में नई ऊंचाइयां छू रहा राजस्थान - मुख्यमंत्री शर्मा

मुख्यमंत्री के नेतृत्व में प्रदेश में कृषि का रोडमैप तैयार, सम्मेलन से नवाचार होंगे साझा, कृषि को मिलेगी नई दिशा : शिवराज सिंह चौहान

जयपुर, (विराट वैभव)। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि कृषि भारत की रीढ़ है तथा किसान इस देश की आत्मा है। केंद्र सरकार किसानों की आय बढ़ाने, उनके जीवन स्तर में सुधार करते हुए कृषि में आत्मनिर्भर बनने के लक्ष्य की ओर तेजी से कार्य कर रही है। उन्होंने राजस्थान में कृषि क्षेत्र में किए जा रहे नवाचारों की तारीफ करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में प्रदेश में कृषि का रोडमैप तैयार किया गया है। चौहान ने अन्य राज्यों को भी इस नवाचार का अनुसरण करने का संदेश दिया।

चौहान ने मंगलवार को जयपुर में आयोजित पश्चिमी क्षेत्रीय सम्मेलन के उद्घाटन सत्र को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि देश की भौगोलिक विविधताओं को ध्यान में रखते हुए प्रधानमंत्री के मार्गदर्शन में क्षेत्रीय कृषि सम्मेलनों के आयोजन का निर्णय लिया गया है। इसी क्रम में पहला क्षेत्रीय कृषि सम्मेलन का शुभारंभ राजस्थान से किया गया है। उन्होंने खेती से जुड़े इस महत्वपूर्ण सम्मेलन का राजस्थान में आयोजन होने पर धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा कि सम्मेलन में गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गोवा तथा राजस्थान राज्य शामिल है तथा इस सम्मेलन में कृषि क्षेत्र की आवश्यकताओं, चुनौतियों और संभावनाओं को समझने का एक मंच मिलेगा। साथ ही, सम्मेलन से राज्यों के बीच आपसी समन्वय व नवाचारों को भी साझा कर कृषि क्षेत्र को नई दिशा मिलेगी।

कृषि का विविधीकरण और एकीकृत कृषि प्रणाली तकनीकों का हो उपयोग-

केंद्रीय कृषि एवं कृषक कल्याण मंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार ने कृषि क्षेत्र के लिए तीन प्रमुख लक्ष्य निर्धारित किए हैं। पहला, देश की खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करना जिससे आत्मनिर्भर भारत के संकल्प को गति मिले। दूसरे लक्ष्य के तहत किसानों की आय बढ़ाने और उनके जीवन स्तर में सुधार पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। साथ ही, तीसरे लक्ष्य के रूप में खाद्य सुरक्षा के साथ-साथ पोषण सुरक्षा सुनिश्चित करने पर जोर दिया गया है। इसके लिए उत्पादन वृद्धि, कृषि का विविधीकरण और एकीकृत कृषि प्रणाली जैसी पहलों के माध्यम से पोषणयुक्त आहार उपलब्ध कराने की दिशा में कार्य किया जा रहा है।

राज्य फार्मर आईडी के तहत 100 प्रतिशत किसानों का करे पंजीकरण-

चौहान ने कहा कि सभी राज्य मिशन मोड पर कार्य करते हुए फार्मर आईडी के तहत शत-प्रतिशत किसानों का पंजीकरण करवाए जिससे किसानों को योजनाओं का लाभ शीघ्रता से मिल सके। प्राकृतिक आपदाओं द्वारा उत्पन्न जोखिमों से किसानों को बचाने के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना संचालित की जा रही है। उन्होंने कहा कि फसलों को हुए नुकसान का शीघ्र आकलन करें, जिससे किसानों को बीमा योजना का लाभ त्वरित मिल सके।

केंद्रीय कृषि योजनाओं के तहत राज्यों को देय राशि में लचीलापन

चौहान ने कहा कि केंद्र सरकार ने यह तय किया है कि देश की कृषि योजनाओं में राज्यों को उनकी भौगोलिक परिस्थितियों के अनुसार देय राशि में लचीलापन दिया जाए, जिससे योजनाओं का बेहतर क्रियान्वयन हो सके। उन्होंने राज्यों को कृषि बजट के तहत आवंटित राशि का प्रभावी उपयोग तथा फसलों की एमएसपी पर समय से खरीद सुनिश्चित करने के लिए भी कहा, ताकि किसानों को राहत मिल सके। उन्होंने कहा कि सभी राज्य विकसित कृषि संकल्प अभियान आयोजित करें जिसमें केंद्र सरकार द्वारा पूरा सहयोग किया जाएगा।

'ग्राम' का आयोजन अच्छी पहल, केंद्र सरकार भेजेगी विशेषज्ञों की टीम-

केंद्रीय कृषि मंत्री ने कहा कि राजस्थान में कृषि की संभावनाओं को देखते हुए कृषि के रोडमैप बनाने की पहल की गई है। अन्य राज्य भी इससे प्रेरणा लेकर कृषि का रोडमैप बनाए। केंद्र सरकार राज्य के इस रोडमैप को और सुदृढ़ बनाने के लिए कृषि वैज्ञानिकों की टीम भेजकर सहयोग प्रदान करेगी, ताकि प्रदेश में कृषि विकास को और गति मिल सके। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार द्वारा आगामी समय में ग्लोबल राजस्थान एग्रीटेक मीट (ग्राम) का भी आयोजन किया जाएगा। जिसमें भी केंद्र सरकार विशेषज्ञों, अधिकारी तथा वैज्ञानिकों की टीम भेजेगी।

ग्लोबल राजस्थान एग्रीटेक मीट से किसानों को मिलेगा लाभ-

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का मानना है कि किसान देश की नींव हैं और देश का विकास गांव की पगडंडियों, खेत-खलियानों से होगा। उन्होंने संवेदनशीलता के साथ किसान हित में निर्णय लेते हुए पीएम किसान सम्मान निधि को बढ़ाया। प्रदेश में हमारी सरकार ने इसमें 3 हजार रुपये और जोड़कर इसे 9 हजार रुपये कर दिया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश को कृषि निर्यात के क्षेत्र में अग्रणी बनाने की दिशा में मई माह में 'ग्लोबल राजस्थान एग्रीटेक मीट-2026' का आयोजन किया जाएगा। इसमें देश-विदेश के कृषि विशेषज्ञों, वैज्ञानिकों और तकनीकी जानकारों को जोड़ा जा रहा है। उन्होंने केंद्र कृषि मंत्री तथा कृषि से जुड़े अन्य गणमान्य विशेषज्ञों को इस सम्मेलन के लिए आमंत्रित किया।

शर्मा ने पश्चिम क्षेत्रीय सम्मेलन का प्रथम आयोजन राजस्थान में करने के लिए कृषि मंत्री को धन्यवाद दिया। उन्होंने विश्वास जताया कि इस सम्मेलन में कृषि विकास के लिए जो वैचारिक मंथन होगा, वह कृषि के भविष्य को नई दिशा देगा। इस कॉन्फ्रेंस में विषयवार प्रस्तुतियों के माध्यम से कृषि उत्पादन, जल प्रबंधन, फसल सुरक्षा, डिजिटल कृषि, प्राकृतिक खेती और किसानों की आय बढ़ाने जैसे विषयों पर होने वाली चर्चा देशभर के विशेष तौर पर राजस्थान के किसानों के लिए विशेष रूप से उपयोगी साबित होगी।

कृषि बजट में की ऐतिहासिक वृद्धि-

मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारी डबल इंजन सरकार किसान हितों के लिए निरंतर कार्य कर रही है। हमने विकसित राजस्थान 2047 की कार्य योजना तैयार की है जिसके तहत फसल श्रेणी वार लक्ष्यों का निर्धारण किया है। हमने कृषि बजट में 34 प्रतिशत की वृद्धि करते हुए वर्ष 2026-27 के लिए 1 लाख 19 हजार 408 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है। उन्होंने कहा कि राजस्थान आज बाजरा, सरसों और ईसबगोल जैसे उत्पादों में देश में प्रथम स्थान पर है, जिसे अब प्रोसेसिंग यूनिट्स के जरिए और अधिक लाभकारी बनाया जाएगा। साथ ही दुग्ध उत्पादन को बढ़ाने पर भी जोर दिया जा रहा है। शर्मा ने कहा कि राजस्थान कृषि में नई ऊंचाइयां छू रहा है। हमारी सरकार द्वारा सिंचाई एवं पेयजल के लिए राम जल सेतु लिंक परियोजना, यमुना समझौता, आईएनजीपी, गंगनहर और सोम-कमला-अम्बा सहित अनेक परियोजनाएं संचालित की जा रही है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि किसानों को अब पारंपरिक तरीकों के स्थान पर वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाने की आवश्यकता है, जिससे कृषि नौकरी और व्यापार से भी अधिक लाभकारी बन सके। मुख्यमंत्री ने किसानों से कृषि में आधुनिक कृषि तकनीक, सिंचाई के लिए फव्वारा सिस्टम और पारंपरिक फसलों के साथ आधुनिक फसलों को शामिल करने का आह्वान किया। साथ ही, उन्होंने रासायनिक उर्वरकों के अंधाधुंध उपयोग पर चिंता जताते हुए मृदा स्वास्थ्य कार्ड के अनुसार खाद प्रयोग करने और भविष्य की पीढ़ियों के लिए भूमि की उर्वरता बनाए रखने की अपील की। उन्होंने कृषि के साथ पशुपालन को जोड़ने पर विशेष बल दिया ताकि प्राकृतिक खाद की उपलब्धता बढ़े और लागत में कमी लाकर किसानों की आय को बढ़ाया जा सके।

गत सरकार के पांच साल की तुलना में हमने 25 माह में किए अधिक काम-

मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारी सरकार ने गत सरकार की तुलना में अधिक काम किए हैं। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार के 25 माह के कार्यकाल में 35 हजार 368 फार्म पौंड बनाए, जबकि गत सरकार ने पहले 25 माह में केवल 8 हजार 152 फार्म पौंड बनाए हैं। इसी तरह हमने 25 माह के कार्यकाल में फार्म पौंड पर कृषकों को 303 करोड़ रुपये का अनुदान दिया और गत सरकार उस समयावधि में केवल फार्म पौंड पर कृषकों को 48 करोड़ रुपये का अनुदान दिया। इसी तरह हमारी सरकार ने खेतों पर तारबंदी, शेडनेट हाऊस, स्वामित्व कार्ड वितरण, डिग्गी निर्माण, गोशालाओं को सहायता सहित विभिन्न कृषि से जुड़े क्षेत्रों में पिछली सरकार की तुलना में कई गुना अधिक कार्य किए हैं।

इस दौरान केंद्रीय कृषि एवं कृषक कल्याण राज्य मंत्री भागीरथ चौधरी, कृषि मंत्री किरोड़ी लाल मीणा, मध्य प्रदेश के कृषि ऐदल सिंह कंसाना, गुजरात के कृषि राज्य मंत्री रमेश भाई कटारा, महाराष्ट्र के कृषि मंत्री दत्तात्रेय विठोबा भरणे, गोवा के सामाजिक कल्याण मंत्री सुभाष उत्तम फल देसाई, मुख्य सचिव वी.निवास, केंद्रीय कृषि सचिव अतिश चंद्रा, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् के महानिदेशक डॉ एम.एल. जाट सहित केंद्र एवं राज्य विभिन्न राज्यों के अधिकारी, कृषि विशेषज्ञ एवं बड़ी संख्या में किसान उपस्थित थे।

नगर निगम की नकारात्मक छवि को बदलने के लिये धरातल पर गुणवक्तापूर्ण रूप से किये जाये कार्य

हर अधिकारी, कर्मचारी की जबावदेही होगी तय, मुख्यालय के बाद जोन स्तर पर सफाई अभियान चलाकर कबाड़ एवं अनुपयोगी सामान का किया जाये निस्तारण : ओम कसेरा आयुक्त

जयपुर, (विराट वैभव)। नगर निगम आयुक्त श्री ओम कसेरा ने मंगलवार को नगर निगम मुख्यालय पर समस्त जोन एवं मुख्यालय उपायुक्त, अधिषाषी अभियन्ता, सहायक अभियन्ता, राजस्व अधिकारी एवं अन्य अधिकारियों की प्रथम बैठक ली। बैठक में आयुक्त ने आमजन के हितों को सर्वोच्च प्राथमिकता देने, कार्यो को धरातल पर गुणवक्तापूर्ण व निर्धारित समयावधि में समयबद्ध रूप से करने के निर्देष दिये। आयुक्त ने प्रथम बैठक में ही स्पष्ट संकेत दिये कि अब कार्यषैली में बदलाव अनिवार्य है। उन्होंने आमजन के हितों को सर्वोच्च प्राथमिकता देने तथा सभी कार्यो को समयबद्ध गुणवक्तापूर्ण एवं प्रभावी तरीके से धरातल पर उतारने के निर्देष दिये।

2 घंटे से भी अधिक चली इस मैराथन बैठक में आयुक्त ने पीपीटी प्रजेटेषन के माध्यम से प्रत्येक शाखा के कार्यो का गहन विषलेषण करते हुये आवष्यक दिषा-निर्देष दिये। बैठक में आयुक्त ने स्वास्थ्य शाखा, स्वच्छ सर्वेक्षण-2026 के अन्तर्गत किये जा रहे कार्य, राजस्व शाखा, पषु प्रबंधन शाखा, उद्यान शाखा, गैराज शाखा, विद्युत शाखा, हैरिटेज सेल द्वारा किये जा रहे कार्य, एसीटीपी प्रकोष्ठ, प्रोजेक्ट शाखा, अग्निषमन शाखा, आयोजना शाखा सहित अन्य शाखाओं के कार्यो व प्रगति के बारे में जानकारी ली।

आयुक्त ने सभी अधिकारियों को सख्त लहजे में कहा कि राजस्थान सम्पर्क पोर्टल पर लंबित षिकायतों का त्वरित निस्तारण सुनिष्चित किया जाये। उन्होंने कहा कि 30 दिन से अधिक समय तक लंबित षिकायतों को सात दिवस में निपटाये तथा 30 दिन से कम समय में लंबित षिकायतों को शीघ्र ही निस्तारण करवाया जाये साथ ही साप्ताहिक रिपोर्ट भी दी जाये। फायर एनओसी प्रक्रिया को सरल एवं पारदर्षी बनाने पर भी विषेष जोर देते हुये उन्होंने आमजन को अनावष्यक परेषानी से बचाने के लिये और लंबित प्रकरणों के शीघ्र निस्तारण के निर्देष दिये।

आयुक्त ने स्पष्ट रूप से कहा कि नगर निगम की नकारात्मक छवि को बदलने का प्रयास करे। आमजन के हितों को सर्वोच्च प्राथमिकता दे। वर्तमान में चल रहे कार्यो को स्पीडअप करने तथा धरातल पर गुणवक्तापूर्ण कार्य करने के निर्देष दिये। अवैध निर्माणों पर लगाम कसे। अस्थाई एवं स्थाई अतिक्रमणों को हटाये विषेष रूप से सरकारी भूमि पर अवैध अतिक्रमण बर्दाष्त नहीं किया जायेगा।

आयुक्त ने कहा कि डोर-टू-डोर कचरा संग्रहण की प्रोपर मॉनिटरिंग की जानी चाहिए जिससे आमजन के घरों पर सही समय पर और निरन्तर रूप से हूपर पहुंचे। आयुक्त ने उपायुक्त राजस्व को निर्देष देते हुये कहा कि वर्ष 2026-27 के राजस्व वसूली के लिये अभी से ही प्रयास किये जाये जिससे शत-प्रतिषत लक्ष्यों को प्राप्त किया जा सके।

आयुक्त ने सभी जोन उपायुक्तों को निर्देष दिये कि जोनों में पड़े कबाड़, अनुपयोगी सामान अगले सात दिनों में निस्तारण किया जाये। आयुक्त ने वर्तमान में चल रहे विकास कार्यो, बजट घोषणाओं की भी जानकारी ली साथ ही समयबद्ध रूप से निर्धारित समयावधि में कार्य करने के निर्देष दिये।

निरीक्षण के बाद देखने को मिला बदलावः-

सोमवार को आयुक्त के निरीक्षण के बाद निगम मुख्यालय में स्पष्ट रूप से बदलाव देखने को मिला, कोने में पड़ी हुई अनुपयोगी सामान व कबाड़ को हटाया गया नगर निगम मुख्यालय पर सफाई अभियान चलाकर सफाई की गई।

सहकारिता विभाग की राज्य स्तरीय समीक्षा बैठक आयोजित : अधिकारी-कर्मचारी पूरे मनोयोग से प्रयास कर अपेक्षित लक्ष्य करें अर्जित

अनियमितताओं के मामलों में दोषियों के विरूद्ध होगी सख्त कार्रवाई : सहकारिता मंत्री

एमएसपी खरीद पूर्ण पारदर्शिता व बिना किसी शिकायत के हो सम्पन्न : शासन सचिव, सहकारिता

जयपुर, (विराट वैभव)। सहकारिता राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) श्री गौतम कुमार दक ने निर्देश दिए कि अधिकारी-कर्मचारी पूरे मनोयोग से प्रयास कर विभागीय कार्यों, योजनाओं एवं गतिविधियों में अपेक्षित लक्ष्य अर्जित करें। जिन जिलों में प्रगति अपेक्षाकृत कम है, उन पर विशेष रूप से फोकस किया जाए। उन्होंने कहा कि अनियमितताओं के मामलों में सख्त रुख अपनाते हुए दोषियों के विरूद्ध कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

श्री दक मंगलवार को शासन सचिवालय स्थित कॉफ्रेन्स हॉल में वीसी के माध्यम से आयोजित सहकारिता विभाग की राज्य स्तरीय समीक्षा बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि सहकारिता क्षेत्र में विश्व की वृहत् अन्न भण्डारण योजना के अंतर्गत बन रहे 500 मीट्रिक टन क्षमता के गोदामों का निर्माण गुणवत्तापूर्ण हो तथा इनका पूर्ण उपयोग सुनिश्चित किया जाए। गोदामों को किराये पर देने के लिए जिला स्तर पर मापदण्ड तय किए जाएं। उन्होंने कस्टम हायरिंग सेंटर्स की स्थापना में भी तेजी लाने के निर्देश देते हुए कहा कि किसानों और सहकारी समितियों को इन सेंटर्स से मिलने वाले लाभ का आकलन किया जाए। साथ ही, कस्टम हायरिंग सेंटर पर उपलब्ध उपकरणों के उपयोग का भी पूरा डेटा तैयार किया जाए।

सहकारिता मंत्री ने पैक्स कम्प्यूटराइजेशन के कार्य में गति लाकर शेष रही सभी समितियों को शीघ्र गो-लाइव करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि जिन जिलों में प्रगति कम है, उनकी सतत मॉनिटरिंग की जाए। साथ ही, गो-लाइव के कार्य में सहयोग नहीं करने वाली समितियों के विरूद्ध कार्रवाई की जाए। श्री दक ने जिला प्रभारियों को नियमित रूप से फील्ड विजिट कर पैक्स स्तर तक विभिन्न कार्यों की जांच के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि अनियमितताओं के मामलों में जो समितियां रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं करवा रही हैं, उनके विरूद्ध एफआईआर दर्ज करवाकर रिकॉर्ड प्राप्त किया जाए।

श्री दक ने सहकारी भूमि विकास बैंकों के बकाया ऋणों की वसूली पर बल देते हुए वसूली कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि इसके लिए अधिकारी स्वयं फील्ड में जाकर ऋणियों से समझाइस करें और निरन्तर फॉलो अप भी करें। एकमुश्त समझौता योजना के अंतर्गत राज्य सरकार ब्याज एवं पेनल्टी माफ कर रही है, ऐसे में बकाया ऋणों की वसूली का यह सुनहरा अवसर है। उन्होंने राज्य स्तर से इसकी नियमित मॉनिटरिंग के निर्देश दिए। साथ ही, फर्जी ऋण वितरण करने वाले कार्मिकों के विरूद्ध एफआईआर दर्ज करवाने के भी निर्देश दिए। श्री दक ने कहा कि प्रत्येक जिले में कम से कम 5 सहकारी समितियां ऐसी हों जो नवीन गतिविधियां शुरू कर मिसाल कायम करें। उन्होंने निर्देश दिए कि सहकारी समितियों को भारतीय बीज सहकारी समिति लि., राष्ट्रीय सहकारी ऑर्गेनिक्स लि. एवं राष्ट्रीय सहकारी निर्यात लि. की सदस्यता के फायदों से अवगत करवाकर सदस्यता में वृद्धि की जाए।

सहकारिता मंत्री ने सहकारी उपभोक्ता भण्डारों पर पैक्स द्वारा तैयार उत्पादों को प्रमोट करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार की मंशा पशुधन से किसानों की आय बढ़ाने की है। इसलिए राजस्थान सहकारी गोपाल क्रेडिट कार्ड योजना का लाभ बिना किसी शिकायत के पात्र किसानों को मिलना चाहिए। उन्होंने कहा कि ऋण प्राप्त करने वाले सभी किसानों से फीडबैक लिया जाएगा। उन्होंने सहकारी बैंकों में डिपोजिट्स बढ़ाने एवं अधिक मात्रा में अकृषि ऋण वितरण करने पर भी फोकस करने के निर्देश दिए।

शासन सचिव एवं रजिस्ट्रार, सहकारिता विभाग डॉ. समित शर्मा ने कहा कि न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद का कार्य पूर्ण पारदर्शिता एवं बिना किसी शिकायत के सम्पन्न होना चाहिए। इसमें किसी भी तरह की कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार द्वारा गेहूं खरीद पर 150 रुपये प्रति क्विंटल की दर से बोनस दिया जा रहा है, जिससे गेहूं की बम्पर खरीद की संभावना है। ऐसे में खरीद से संबंधित सभी तैयारियां पूरी रखी जाएं।

शासन सचिव ने निर्देश दिए कि जनसुनवाई में प्राप्त प्रकरणों एवं शिकायतों का निर्धारित समय सीमा में निस्तारण किया जाए, राज सहकार पोर्टल का पूर्ण उपयोग सुनिश्चित किया जाए तथा समस्त कार्य ई-फाइल के माध्यम से किया जाए। उन्होंने कहा कि सहकारी संस्थाओं में पारदर्शिता बढ़ाया जाना अपेक्षित है। उन्होंने सभी अधिकारियों एवं निरीक्षकों के लक्ष्य निर्धारित कर प्रगति के आधार पर रैंकिंग सिस्टम लागू करने पर भी जोर दिया। बैठक में भूमि विकास बैंकों के कम्प्यूटराइजेशन, अवसायनाधीन समितियों के अवसायन, नवीन डेयरी सहकारी समितियों के गठन एवं नवगठित पैक्स के रजिस्ट्रेशन आदि बिन्दुओं पर भी समीक्षा की गई।

राजफेड के प्रबंध निदेशक श्री सौरभ स्वामी सहित सभी शीर्ष सहकारी संस्थाओं के प्रबंध निदेशक एवं फंक्शनल अधिकारी बैठक में उपस्थित रहे। जबकि, समस्त अतिरिक्त रजिस्ट्रार (खण्ड), क्षेत्रीय अंकेक्षण अधिकारी (खण्ड), जिला उप रजिस्ट्रार, केन्द्रीय सहकारी बैंकों के प्रबंध निदेशक, विशेष अंकेक्षक, प्राथमिक भूमि विकास बैंकों के सचिव, क्रय-विक्रय सहकारी समितियों के सीईओ एवं जिला इकाइयों में कार्यरत निरीक्षक वीसी के माध्यम से बैठक में शामिल हुए।

चूरू-सादुलपुर रेलखण्ड पर दुधवाखारा-हड़याल-डोकवा-सादुलपुर स्टेशनों के मध्य दोहरीकरण कार्य

कार्य के कारण रेलसेवाएं आंशिक रद्द रहेगी

जयपुर (विराट वैभव)। रेलवे द्वारा बीकानेर मंडल के चूरू-सादुलपुर रेलखण्ड के मध्य दुधवाखारा-हड़याल- डोकवा-सादुलपुर स्टेशनों के मध्य दोहरीकरण कार्य के लिए ऑटोमेटिक सिंगनलिग ब्लॉक लिया जा रहा है। इस कार्य हेतु रेलसेवाओं को मार्ग परिवर्तित किया जा रहा है। उत्तर पश्चिम रेलवे के मुख्य जन सम्पर्क अधिकारी श्री अमित सुदर्शन के अनुसार उपरोक्त कार्य के कारण उत्तर पश्चिम रेलवे की निम्न रेलसेवाएं प्रभावित रहेगीः-

आंशिक रद्द रेलसेवाएं (प्रारम्भिक स्टेशन से)

1. गाडी संख्या 14891, जोधपुर-हिसार रेलसेवा जो दिनांक 14.04.26 को जोधपुर से प्रस्थान करेगी वह रतनगढ तक ही संचालित होगी। अर्थात् यह रेलसेवा रतनगढ-हिसार के मध्य आंशिक रद्द रहेगी।
2. गाडी संख्या 14892, हिसार-जोधपुर रेलसेवा दिनांक 15.04.26 को हिसार के स्थान पर रतनगढ से संचालित होगी। अर्थात् यह रेलसेवा हिसार-रतनगढ के मध्य आंशिक रद्द रहेगी।

नोट- उक्त रेलसेवाओं को पूर्व प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार चुरू-हिसार-चुरू के मध्य भी आंशिक रद्द किया गया है।

बुलेट ट्रेन परियोजना कार्य के कारण अहमदाबाद मंडल से गुजरने वाली 4 ट्रेनें प्रभावित

अहमदाबाद (विराट वैभव)। पश्चिम रेलवे के अहमदाबाद मंडल में नेशनल हाई स्पीड रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड (NHSRCL) की बुलेट ट्रेन परियोजना के अंतर्गत गेरतपुर-अहमदाबाद रेलखंड पर प्रीकास्ट पोर्टल बीम स्थापित करने हेतु आवश्यक कार्य किया जाना प्रस्तावित है। इस कार्य के लिए दिनांक 08 अप्रैल, 2026 को ट्रैफिक ब्लॉक लिया जाएगा।

इस ट्रैफिक ब्लॉक के चलते अहमदाबाद मंडल से गुजरने वाली निम्नलिखित ट्रेनें प्रभावित रहेंगीः

रद्द ट्रेनें:

ट्रेन संख्या 22959 वडोदरा-जामनगर इंटरसिटी एक्सप्रेस, जो अहमदाबाद मंडल के अहमदाबाद, साबरमती, चांदलोड़िया, आंबली रोड एवं वीरमगाम स्टेशनों से होकर चलती है, दिनांक 08.04.2026 को रद्द रहेगी।

ट्रेन संख्या 22960 जामनगर-वडोदरा इंटरसिटी एक्सप्रेस, जो अहमदाबाद मंडल के वीरमगाम, आंबली रोड, चांदलोड़िया, साबरमती एवं अहमदाबाद स्टेशनों से होकर चलती है, दिनांक 09.04.2026 को रद्द रहेगी।

मार्ग में रेगुलेट होने वाली ट्रेनें:

ट्रेन संख्या 22718 सिकंदराबाद-राजकोट सुपरफास्ट एक्सप्रेस, जो अहमदाबाद मंडल के मणिनगर, अहमदाबाद एवं वीरमगाम स्टेशनों से होकर चलती है, दिनांक 08.04.2026 को वडोदरा मंडल में लगभग 01 घंटे के लिए रेगुलेट की जाएगी।

ट्रेन संख्या 15636 गुवाहाटी-ओखा एक्सप्रेस, जो अहमदाबाद मंडल के अहमदाबाद एवं वीरमगाम स्टेशनों से होकर चलती है, दिनांक 08.04.2026 को वडोदरा मंडल में लगभग 01 घंटे के लिए रेगुलेट की जाएगी।

यात्रियों से अनुरोध है कि ट्रेनों के समय, ठहराव एवं अन्य अद्यतन जानकारी के लिए www.enquiry.indianrail.gov.in का अवलोकन करें।

NHSRCL परियोजना कार्य के चलते अहमदाबाद मंडल की ट्रेनें प्रभावित

अहमदाबाद (विराट वैभव)। पश्चिम रेलवे के अहमदाबाद मंडल में National High Speed Rail Corporation Limited (NHSRCL) परियोजना के अंतर्गत गेरतपुर-अहमदाबाद रेलखंड पर प्रीकास्ट पोर्टल बीम स्थापित करने हेतु आवश्यक कार्य किया जाना प्रस्तावित है। इस कार्य के लिए दिनांक 08 अप्रैल, 2026 (बुधवार) को ट्रैफिक ब्लॉक लिया जाएगा। जिसके कारण अहमदाबाद मंडल से संबंधित ट्रेनें प्रभावित रहेंगी।

SUPREME HOME LOANS
सुप्रीम हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड
रजि. ऑफिस : दूसरी मंजिल, हर्षा भवन, 13/29, ई-ब्लॉक, मिडिल सर्कल, कनॉट प्लेस, नई दिल्ली - 110001
CIN: U67190DL2014PLC272457; टेलीफोन नंबर: +9111-41323147
ईमेल ; customercare@supremehomeloans.com वेबसाइट: www.supremehomeloans.com

सूचना

भारतीय रिज़र्व बैंक (गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां शाखा प्राधिकरण) निर्देश, 2025 दिनांक 28 नवंबर, 2025 के अनुसार, यह सूचित किया जाता है कि कंपनी का शाखा कार्यालय, जो **फर्स्ट फ्लोर, श्री नाथ चैम्बर्स, 11-ए, नई ग्रेन मंडी, कोटा, राजस्थान 324007** में स्थित है, 13 जुलाई 2026 को कार्य समय समाप्त होने के बाद बंद कर दिया जाएगा, क्योंकि इसका संचालन निकटवर्ती शाखा कार्यालय, **सेकंड फ्लोर, राघव काम्प्लेक्स, नियर एक्सिस बैंक, जोशी मीणा कॉलोनी 1, केकरि, अजमेर जिला, राजस्थान 305404** में स्थानांतरित किया जा रहा है। यदि किसी सहायता की आवश्यकता हो, तो आप उल्लिखित निकटतम शाखा कार्यालय से संपर्क कर सकते हैं या ईमेल भेज सकते हैं-customercare@supremehomeloans.com.
यह सूचना कंपनी की वेबसाइट पर देखी जा सकती है (www.supremehomeloans.com).

फॉर एंड ओन बेहल्फ़ ऑफ सुप्रीम हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड
तारीख: 08.04.2026
हस्ताक्षर/- नेहा भाटिया कंपनी सचिव